

ग्रामीण भारत के विकास में
कृषि की भूमिका
(Role of Agriculture in the Development
of Rural India)

सम्पादक

डॉ० गगन कुमार

असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग
राजकीय महाविद्यालय पिहानी, हरदोई (उ०प्र०)

डॉ० सुरेन्द्र कुमार

असिस्टेंट प्रोफेसर, गणित विभाग
राजकीय महाविद्यालय पिहानी, हरदोई (उ०प्र०)



प्रभाश्री विश्वभारती प्रकाशन
इलाहाबाद (उ.प्र.)

- प्रथम संस्करण : 2016
- मूल्य : ₹ 500/-
- ISBN : 978-93-83519-35-4
- इस संदर्भ पुस्तक में प्रकाशित शोध पत्रों में प्रस्तुत विचार, विशुद्ध रूप से शैक्षणिक एवं व्यक्तिगत रूप से लेखक के हैं, जिनका न ही सम्पादक व प्रकाशक का इससे कोई सम्बन्ध है और न ही किसी शासकीय नीति की अभिव्यक्ति से।
ई-मेल से प्राप्त शोध-पत्रों के प्रकाशन में यथा संभव सावधानी बरती गई है किन्तु प्रकाशन में त्रुटिवश किसी टंकण त्रुटि के लिए सम्पादक/महाविद्यालय उत्तरदायी नहीं है।
- प्रकाशक :
प्रभाश्री विश्वभारती प्रकाशन
इलाहाबाद (उ.प्र.)
- मुद्रक :
प्रभा कम्प्यूटर्स एण्ड प्रिंटर्स
इलाहाबाद (उ.प्र.) # 9450252918

प्राक्कथन

इस पुस्तक के प्रकाशन में हमारा सहयोग एवं मार्गदर्शन करने वाले सभी सहयोगियों एवं महानुभावों का हृदय से आभार।

सर्वप्रथम में उन सभी विद्वतजनों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपने ज्ञान एवं अनुभवों द्वारा इस पुस्तक के संपादन में अपना अमूल्य योगदान दिया, जिसके फलस्वरूप इस पुस्तक का सफलतापूर्वक प्रकाशन समयान्तर्गत पूर्ण हो सका।

मैं अपने सभी सहयोगियों, सहकर्मियों, मित्रों व शोधार्थियों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने समय-समय पर अपने बहुमूल्य सुझावों व सहयोग प्रदान कर इस कार्य को पूर्ण करने में अपना विशेष योगदान दिया।

इस पुस्तक के लेखों व शोधपत्रों के सम्पादन के लिए मैं प्राचार्य डॉ. सुधीर कुमार चौहान, डॉ. सुरेन्द्र कुमार व श्री आशीष सिंह द्वारा किए विशेष सहयोग के लिए आभारी हूँ।

इस पुस्तक का प्रकाशन, प्रकाशक द्वारा की गई मेहनत का प्रतिफल है।

अतः इस पुस्तक के प्रकाशक राजेश शर्मा, प्रभा कम्प्यूटर्स एण्ड प्रिंटर्स के प्रति मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

डॉ. गगन कुमार

भूमिका

मानव सभ्यता के विकास के क्रम में, कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसका महत्व दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही गया है। देश को आजाद हुए 69 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और स्वाधीनता के 69 वर्षों में देश ने बहुत तरक्की की है। महानगरों से लेकर गाँवों तक में स्थितियाँ काफी बदली है। गाँव पहले से कहीं ज्यादा समृद्ध हुए हैं और ग्रामीण पहले से अधिक जागरूक।

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और प्राचीन काल से भारतीय कृषि का स्वरूप जीवन निर्वाह ही रहा है। कृषि को लाभदायक बनाने के लिए निरन्तर प्रयास किये गए किन्तु हम आज भी कृषि का कोई ऐसा मॉडल विकसित नहीं कर पाए हैं जिससे किसानों के लिए कृषि को लाभदायक बनाया जा सके। कृषकों के पिछड़ेपन का मुख्य कारण कृषकों का अशिक्षित होना प्रशिक्षण का अभाव व सूचना का अभाव है, कुछ शिक्षित, प्रशिक्षित व सक्रिय कृषक ही आज प्रगतिशील खेती कर पा रहे हैं।

भूमंडलीकरण के इस दौर में कृषि, उद्योग व व्यापार के क्षेत्र में देश ने बहुत विकास किया है। शहरों में जहाँ जनसंख्या के अनुपात में रोजगार के अवसर कम हुए हैं वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी रोजगार के कई साधन उपलब्ध है। कौशल विकास, स्वयं सहायता समूह व मनरेगा के माध्यम से ग्रामीणों में आत्मनिर्भरता व चेतना आयी है। यही कारण है कि आज गाँवों में शहर जैसी सुविधाएँ मिलने लगी है और कई बड़े गाँव देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। कृषि आधारित रोजगार से जुड़कर नवयुवक भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रहे हैं। कृषि आधारित उद्योगों से जुड़ने से कृषि आधारित उद्योगों में नए अवसर सृजित हुए हैं।

भूमंडलीकरण के इस युग में कृषि का व्यवसायीकरण एक अनिवार्य वास्तविकता है। प्रतियोगिता में बने रहने के लिए जरूरी है कि कृषि वस्तुओं में विविधता एवं गुणवत्ता हो इसलिए यह अति आवश्यक है कि कृषि को उद्योग का दर्जा मिले और सहायिकी की राशि बढ़े और किसानों के पुराने कर्ज पूरी तरह से माफ हो।

आज के किसानों को मिट्टी की जाँच से लेकर पूँजी और तकनीकी के बेहतर उपयोग के बारे में प्रशिक्षित करना अनिवार्य है जिससे कृषि को लाभकारी बनाया जा सके। साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन, सूखा और बाढ़ या अन्य कारणों से बर्बाद हुयी फसलों पर फसल बीमा योजना का पूर्ण लाभ मिले जिससे कृषि को लाभ का सौदा बनाया जा सके। ग्रामीण भारत के विकास में कृषि के समक्ष चुनौतियों को दूर कर हमें इसके लिए नयी संभावनाएँ तलाशनी होगी।

डॉ. गगन कुमार

अनुक्रमणिका

प्राक्कथन	iii
भूमिका	iv
अनुक्रमणिका	v

ग्रामीण भारत के विकास में कृषि की भूमिका

● ग्रामीण विकास एवं सशक्तीकरण में मनरेगा की भूमिका डा. हेमलता	1
● भारत में खाद्य सुरक्षा एवं कृषि कीमत नीति डॉ. पुन्ज भाष्कर	6
● कृषि और किसानों की दशा में बुनियादी बदलाव और नई नीति डॉ. पुन्ज भाष्कर, डॉ. ज्ञानेन्द्र जी श्रीवास्तव	15
● भारत में कृषि : चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ डा. चैतन्य कुमार	20
● भारतीय कृषि के उत्पादन का अध्ययन डॉ. ज्योतिका अवस्थी, डॉ. उपज्ञा	25
● कृषि का सशक्तीकरण—समाजशास्त्रीय अध्ययन डा. नीलम टण्डन	30
● भारत में ग्रामीण कृषि साख व्यवस्था : चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ मेवा लाल	34
● सरकारी नीतियों का कार्यान्वयन और किसानों की दशा प्रभाकर यादव	46
● सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में उच्च शिक्षा की भूमिका डॉ. कृष्ण देव उपाध्याय	53

- ग्रामीण भारत में कृषि आधारित उद्योगों की भूमिका 57
उर्वशी श्रीवास्तव, डा. पुनीत कुमार श्रीवास्तव 'मनीषी', इन्द्रपीत कौर
- जलवायु परिवर्तन का भारतीय कृषि पर प्रभाव 63
एक भौगोलिक अध्ययन
चन्द्रप्रभा
- ग्रामीण विकास में पंचायती राज व्यवस्था का प्रभाव 69
डा. रीतू शाही, शेखर सिंह
- ग्रामीण विकास में मनरेगा का प्रभाव 75
डॉ. सरिता वर्मा
- भारतीय विकास में कृषि की भूमिका : चुनौतियां एवं सम्भावनाएं 80
डॉ. नीतू सिंह तोमर
- जलवायु परिवर्तन एवं संपोषणीय कृषि 87
विजय अग्रवाल, डा. पुनीत कुमार श्रीवास्तव 'मनीषी'
- हिन्दी कथा साहित्य और कृषक 91
डॉ. अनुपमा
- ग्रामीण भारत के विकास में कृषि की भूमिका 96
गौतम गुप्ता
- ग्रामीण भारतीय समाज में कृषि विकास के माध्यम से 102
गरीबी उन्मूलन की संभावनाएं
डॉ. दीप्तिमा, डॉ. विक्रम सिंह
- The Importance of Rural Deveopment in the 21st Century 112
Dr. S.K. Chauhan, Abhay Jain
- Role of Science & Technology in Rural 127
Development of India
Ashish Singh, Dr. Surendra Kumar
- Role of Employment in Indian Agricultural 132
Dr. Gagan Kumar, Priyanka Bharti

- Emerging Technology and Crop Diversification 136
Santan Kumar Ram
- Challenges for the National Food Security Act. 140
Ratan lal, Vikas Pradhan
- Agrarian India & Physical Fitness Activity-'Kushti' : 158
An Overview
Dr. Sarita Yadav
- Agriculture and the Weather God 163
Anupma Singh
- Effect of Organic Agriculture on Sustainable 169
Development of Indian Economy
Aparna Gautam
- Dr. B.R. Ambedkar's thoughts on 174
Indian Agriculture system.
Chitade Nandkishor P., Munde B.R.
- The Impact of Climate Change and Climatic Variability 176
on Agriculture Productivity in India
Dr. Kumar Amit
- Role of e-commerce in Socio-Economic Development 184
Nidhi Soni
- Agriculture and Rural Development : Need of the 193
21st century
Devendra Kumar Maurya, Sapna Maurya

ग्रामीण विकास में पंचायती राज व्यवस्था का प्रभाव

डा. रीतू शाही*, शेखर सिंह†

पंचायती राज व्यवस्था लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण का अभिन्न अंग है। भारत के संघात्मक शासन में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के रूप में पंचायती राज व्यवस्था वास्तविक प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रकट रूप है।

वैसे तो भारत में स्थानीय शासन प्राचीन काल विशेषकर मौर्य काल में देखने को मिलता है किन्तु मूलतः आधुनिक स्थानीय स्वशासन का संगठन, कार्य प्रणाली और विकास ब्रिटिश राज की देन है। लार्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जन्म दाता माना जाता है।

स्वतंत्रता के पश्चात भारत में स्थानीय स्वशासन को लेकर दो तरह की विचार धाराएं थीं। प्रथम महात्मा गाँधी की जो पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्था को निर्धन ग्रामीण भारतीयों के प्रतिकूल मानते थे तथा पंचायती राज व लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के अनुकूल मानते थे। जबकि दूसरी विचार धारा के समर्थक पण्डित नेहरू व डा० अम्बेडकर थे जिन्होंने पंचायती राज का अलग-अलग कारणों से विरोध किया। प० नेहरू का जोर पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्था पर ज्यादा था। जबकि डा० अम्बेडकर ने गावों को शोषण की संस्था माना है। उनके अनुसार पंचायतों को सत्ता सौपना जमींदारों को सौपना है।

महात्मा गाँधी की चिंता को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान के राज्य के नीति-निदेशक तत्वों के रूप में अनुच्छेद 40 में पंचायती राज को स्थान दिया गया। फलतः सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953 के माध्यम से पंचायती राज को लागू करने का प्रयास किया गया। परन्तु इस कार्यक्रमों की असफलता के बाद सरकार ने 1957 में बलवन्त राय मेहता समिति 1957 का गठन किया। जिसने लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की योजना के अन्तर्गत पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। इस समिति ने पंचायती राज सम्बन्धी तीन स्तरीय पद्धति — ग्राम पंचायत, समिति ब्लाक पंचायत एवं जिला पंचायत का सुझाव दिया। इन सिफारिशों के परिपेक्ष्य में इनका कार्यान्वयन सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को किया गया। इसी सन्दर्भ में जनता सरकार ने

* असि. प्रो. राजनीति विज्ञान, आर. एम. पी. स्नात महा. सीतापुर

† असि. प्रो. राजनीति विज्ञान, दीन दयाल उपा. राज स्नात महा. सीतापुर

1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया जिसने द्विस्तरीय पंचायत की सिफारिश की थी। इसीक्रम में ग्रामीण विकास एवं निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए योजना आयोग द्वारा 1985 में जी.वी.के राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। 1986 में राजीव गाँधी सरकार ने लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर एल0 एम0 सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। जिसने पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में विशेष स्थान देने की बात कही। सर्वप्रथम पी.के.थुंगन समिति 1988 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिये जाने की बात कही। फलस्वरूप 1989 के चौसठवाँ संविधान संशोधन विधयक के पास ना होने के बाद केन्द्र सरकार ने पंचायती राज की बुनियादी विशेषताओं को मजबूत आधार प्रदान करते हुए 22 दिसम्बर 1992 को ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधयक 73 वाँ संशोधन पारित करके पंचायती राज को नई दिशा प्रदान की, इसकी प्रमुख सिफारिशें हैं :-

- 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायतें।
- पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष।
- सभी स्तरों पर सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष हुआ।
- महिलाओं के लिए कुल स्थानों का एक तिहाई आरक्षित रहेगा।
- संविधान में ग्यारहवीं अनुसूची का निर्माण किया गया जिसमें 29 विषयों को रखा गया।
- राज्य वित्त आयोग तथा राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया।

73 वें संविधान संशोधन के बाद ग्रामीण विकास में पंचायती राज व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन किया है। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से स्थानीय लोग न केवल नीति का निर्धारण करते हैं अपितु उसके क्रियान्वयन व प्रशासन का नियंत्रण एवं मार्ग दर्शन भी करते हैं।

73 वें संशोधन के बाद पंचायती राज व्यवस्था ने ग्रामीण राजनीतिक विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। इसमें महिलाओं को एक तिहाई तथा अनुसूचित जाति व जनजाति को उनके आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व दिया गया है। इस संशोधन के पूर्व पंचायत पदों पर अनुसूचित जाति व महिला का प्रतिनिधित्व न के बराबर था।

Percentage of reservation category of chairpersons in Panchayat
Ele.-2000

S.N.	Name of the Post	Category	Reservation Category in percent		
			Female	Male	total
1.	Pradhan Gram Panchayat	Sch. Tribe	0.02	0.04	0.06
		Sch. Caste	8.05	13.71	21.76
		Obc	11.88	21.68	33.56
		Gen	15.37	29.25	44.62
		Total	35.32	64.68	100.00
2.	Pramukh Khetra Panchayat	Sch. Tribe	----	-----	-----
		Sch. Caste	9.89	10.01	19.90
		Obc	12.75	15.58	28.31
		Gen	14.09	37.70	51.79
		Total	36.71	63.29	100.00
3.	Adhyash Zila Panchayat	Sch. Tribe	---	---	---
		Sch. Caste	13.04	7.25	20.29
		Obc	15.94	15.94	31.88
		Gen	24.64	23.19	47.83
		Total	53.62	46.38	100.00

वहीं 73 वें संविधान संशोधन के बाद 2000 के पंचायत निर्वाचन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व एक तिहाई से बहुत ज्यादा विभिन्न पदों पर परिलक्षित हो रहा है। उपरोक्त आंकड़ों से भी यह स्पष्ट है :-

वर्तमान समय में पंचायत चुनाव अनारक्षित सीटों पर भी महिला, अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व आश्चर्य जनक रूप से बढ़ा है। जो एक नये ग्रामीण भारत की तस्वीर पेश कर रहा है।

विशेष नोट: 1. 2003-04 के अन्तर्गत निर्वाचन परिणामों को भूगोलीय अर्थशास्त्र के आधार पर विवरण

क्र. सं.	राज्य	ग्रामीण क्षेत्रों की संख्या	ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या	अनुसूचित जातों की आबादी (संख्या)						ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी (संख्या)						कुल जनसंख्या
				अनुसूचित जातों की संख्या		अनुसूचित जातों की जनसंख्या		ग्रामीण क्षेत्रों की संख्या		ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या		ग्रामीण क्षेत्रों की संख्या		ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या		
				पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	
1	सर्व राज्य	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	सर्व राज्य	652549	651069	581	345	90995	69971	120111	95314	199739	94673	401426	250243	651666		
2	पंजाब	52001	51976	40	61	6943	4961	7852	12536	11038	8545	25873	26103	51976		
3	हरियाणा	65087	65080	61	53	9833	6340	14670	9219	15636	9268	40200	24890	65080		
4	राजस्थान	2631	2628	1	1	358	271	597	409	615	376	1571	1057	2628		
5	गुजरात	820	818	0	1	73	108	138	190	183	125	394	424	818		
6	महाराष्ट्र	820	819	0	0	33	20	228	92	310	136	571	248	819		
7	कर्नाटक	820	818	0	0	97	37	224	89	256	115	577	241	818		
8	आंध्र प्रदेश	70	70	0	0	5	10	8	28	4	15	17	52	70		
9	उत्तर प्रदेश	774798	773878	683	461	108337	61718	143828	107877	217781	113123	470629	303243	773878		

पंचायत निर्वाचन 2005-06 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण स्तर पर सामाजिक परिवर्तन में प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है। विभिन्न वर्गों व जातियों का प्रतिनिधित्व समान रूप से होने के कारण छूआ छूत व ऊंच नीच के बन्धन शिथिल हो रहे हैं। आज महिलाएं प्रधान पती जैसे शब्दों से ऊपर आकर स्वयं निर्णय ले रही हैं। न केवल कम पढ़े लिखे अपितु उच्च शिक्षित व्यक्ति भी पंचायती राज व्यवस्था में सक्रिय रूप से अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। जो ग्रामीण विकास के लिए शुभ संकेत है। उदाहरण स्वरूप राजस्थान में उच्च शिक्षित प्रबंधन की छात्रा ने पंचायत मुखिया के पद का सफलता पूर्वक निर्वहन किया है।

केन्द्र तथा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का संचालन ग्रामीण विकास हेतु पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। जिसमें महात्मा गाँधी रोजगार गारंटी योजना, शौचालय निर्माण (स्वच्छ भारत अभियान), ग्रामीण आवास निर्माण (इन्दिरा आवास) तथा विभिन्न पेंशन योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं ने ग्रामीण विकास को एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया है। मनरेगा में दस वर्षों में (2006-2016) ग्रामीण रोजगार हेतु 3.13 लाख करोड़ रुपया खर्च किए गये। जिसमें 71 प्रतिशत धनराशि मजदूरों के मानदेय पर खर्च की गई है। ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की तरफ मजदूरों का पलायन रूक सके तथा रोजगार की प्रचुरता स्थानीय ग्रामीण स्तर पर ही हो सके। मनरेगा योजना के तहत न केवल पुरुषों अपितु महिलाओं की भी भागीदारी उत्तरोत्तर बढ़ी है। राजस्थान तथा आन्ध्रप्रदेश में महिला जॉब कार्ड धारकों की संख्या क्रमशः 68 व 59 प्रतिशत तक रही है। (2014-2015 में)

वर्तमान समय में भारत सरकार की महात्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत ग्रामीण स्तर पर शौचालय का निर्माण युद्ध स्तर पर जारी है। जिसके लिए केन्द्र सरकार समुचित नगद राशि उपलब्ध करा रही है। इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत ग्रामीण स्तर पर कमजोर वर्गों के लिए आवास निर्माण हेतु सरकार सत्तर हजार रुपए सब्सिडी प्रदान करती है। जो ग्रामीण परिसम्पत्तियों के निर्माण में सहायक होता है।

इसके अतिरिक्त विभिन्न पेंशन योजनाएं यथा वृद्धावस्था, विधवा, समाजवादी ग्रामीण स्तर पर आर्थिक विकास में सहायक हैं।

पंचायत राज व्यवस्था भारत के ग्रामीण विकास में बड़े बदलाव के साथ एक महत्वपूर्ण औजार साबित हो रहा है। पंचायत निर्वाचन में लोगों की बढ़ रही भागीदारी इसकी सफलता को बयां कर रही है।

इन उपलब्धियों के साथ-साथ ग्रामीण विकास में पंचायती राज व्यवस्था में धन बल का बढ़ता प्रभाव चिन्ता उत्पन्न कर रहा है। पुनः चुनावों से गाँवों में वैमनस्यता व हिंसा सामाजिक समरसता को क्षति पहुंचा रहे हैं। फिर भी

ग्रामीण विकास में पंचायती राज व्यवस्था मील का पत्थर साबित हो रही है । इसके साथ जरूरत इस बात की भी है कि पंचायती राज के कार्यक्रम में इस तरह का बदलाव लाया जाए जो सामाजिक न्याय के साथ-साथ आर्थिक रूप से टिकाऊ परिसम्पत्तियों का निर्माण कर सके ।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. भारतीय प्रशासन – अवस्थी एवं अवस्थी
2. महिला विकास एक मूल्यांकन – प्रो.मधूसूदन त्रिपाठी
3. भारतीय प्रशासन – श्री राम माहेश्वरी
4. राजनीति विज्ञान – एन.डी.अरोड़ा
5. भारतीय संविधान – डी.डी.बसु
6. भारतीय संविधान – सुभाष कश्यप
7. भारतीय संविधान – बेयर एक्ट प्रयाग पुस्तक सदन
8. राज्य निर्वाचन आयोग की अधिकृत वेबसाइट
9. अमर उजाला
10. दैनिक जागरण